



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244879  
CG-DL-E-01042023-244879

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

No. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

मामला संख्या: एडी (ओआई) - 03/2023

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम साइनाइड (एनएसीएन)' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 6/03/2023-डीजीटीआर.**—हिंदुस्तान केमिकल कंपनी और यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार एक आवेदन एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने और "सोडियम साइनाइड (एनएसीएन)" (इसके बाद 'संबंधित सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में संदर्भित) के आयात पर उपयुक्त एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए चीन पीआर, यूरोपीय संघ (बाद में 'ईयू' के रूप में संदर्भित), जापान और कोरिया आरपी (बाद में 'संबद्ध देशों' के रूप में संदर्भित) से निर्यात किया गया दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, जो संबद्ध देशों में मूल रूप से या वहां से निर्यात किए गए हैं और उन्होंने संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

#### **क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'सोडियम सायनाइड' है जो मामूली रूप से मजबूत बेस है। यह NaCN सूत्र वाला एक जहरीला यौगिक है। यह सफेद रंग का होता है और पानी में घुलनशील ठोस होता है। साइनाइड केशन में धातुओं के लिए एक उच्च संबंध है, इस प्रकार, इस आधार के लिए उच्च विषाक्तता का श्रेय दिया जाता है।
4. **प्रयोग:** सोडियम सायनाइड का उपयोग उनके संबंधित अयस्कों से सोने और चांदी की निकासी के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातुओं के ताप उपचार (केस हार्डनिंग), कीटनाशकों, रंगों, पिगमेंट, थोक दवाओं के निर्माण और कई कार्बनिक संश्लेषणों, एग्रीकेमिकल्स, नायलॉन इंटरमीडिएट्स, जेलिंग यौगिकों अयस्क प्लवनशीलता और दवा मध्यवर्ती में किया जाता है।
5. **टैरिफ वर्गीकरण:** विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्षक 283711 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, अतीत में, पीयूसी को अन्य उप-शीर्षों के तहत भी आयात किया गया है, जैसे कि 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 और 28371910।
6. जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और एंटी-डंपिंग एप्लिकेशन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

#### **ख. समान वस्तु**

7. आवेदकों ने कहा है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु को चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया आरपी से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

#### **ग. संबद्ध देश**

8. आवेदन मूल रूप से चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य में मूलतः या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के संबंध में दायर किया गया था। तत्पश्चात, प्रथम दृष्टया जांच के दौरान, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर जांच दल ने यह सुनिश्चित किया कि जर्मनी से आयात भी न्यूनतम सीमा से अधिक है और घरेलू बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य हैं।

#### **घ. जांच की अवधि (पीओआई)**

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (इसके बाद पीओआई के रूप में संदर्भित) 1 अक्टूबर 2021 - 30 सितंबर 2022 (12 महीने) है। इसके अलावा, क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2019- 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020- 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021- 31 मार्च 2022 और पीओआई के रूप में प्रस्तावित की गई है।

#### **ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

10. आवेदन हिंदुस्तान केमिकल कंपनी और यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वे भारत में समान वस्तु के केवल उत्पादक हैं।
11. आवेदकों ने आधार वर्ष और उसके बाद के वर्ष में संबद्ध वस्तु का आयात किया था। तथापि, किसी भी आवेदक ने जांच की अवधि में या ठीक पिछले वर्ष में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, कोई भी आवेदक संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के क किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

12. इसलिए, आवेदक घरेलू उत्पादक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

### **च. कथित पाटन का आधार**

#### **13. सामान्य मूल्य**

##### **I. चीन पीआर**

- i. आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया है कि चीन जन गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन गण के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन गण के उत्पादक यह न दर्शाएं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध - I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. इसलिए, उचित लाभ मार्जिन के साथ, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ विधिवत समायोजित आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

##### **II. यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया आरपी**

- i. आवेदकों ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया आरपी में कीमत से संबंधित डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।
- ii. इसलिए, शुरुआत के प्रयोजन के लिए, उचित लाभ मार्जिन के साथ, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ विधिवत समायोजित आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। प्राधिकारी जांच के दौरान सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए हितबद्ध पक्षकारों और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की आगे जांच करेंगे।

#### **14. निर्यात कीमत**

- i. संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डीजीसीआईएंडएस प्रकाशित आयात डेटा के आधार पर की गई है, जिसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क शामिल हैं, ताकि शुद्ध निर्यात मूल्य निकाला जा सके।

#### **15. पाटन मार्जिन**

- i. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

### **छ. क्षति और कारणात्मक संबंध**

16. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से और साथ ही सापेक्ष दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से संबद्ध देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक और अत्यधिक है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण कीमतों में हास और हास घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूल करने और प्रतिलाभ की उचित दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रहे हैं। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उस मांग से कम है जिसे वह पूरा कर सकता है। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग के मालसूची स्तरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवेदकों की उत्पादकता उत्पादन में बदलाव के साथ आगे बढ़ी है। आवेदक की वृद्धि मात्रा के साथ-साथ मूल्य मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक रही है।
17. संबद्ध आयातों का आयात मूल्य बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ा है, जिससे मांग और आपूर्ति में कोई अंतर न होने के बावजूद संबद्ध देशों से निरंतर आयात की अनुमति मिलती है। आयात की लगातार कम कीमत ने आवेदकों को अपनी क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। परिणामस्वरूप, आवेदक निष्क्रिय क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।

### **ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

18. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

### **झ. प्रक्रिया**

19. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत यथावर्णित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**घ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों **dd11-dgtr@gov.in** और **dd16-dgtr@gov.in** पर तथा उनकी एक प्रति **adg14-dgtr@gov.in** और **adv13-dgtr@gov.in** को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जांच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

**ट. समय-सीमा**

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों **dd11-dgtr@gov.in** और **dd16-dgtr@gov.in** तथा **adg14-dgtr@gov.in** और **adv13-dgtr@gov.in** को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

28. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. इच्छुक पक्ष आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

**ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण**

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

**ढ. असहयोग**

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2023

Case No. AD(OI) – 03/2023

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of 'Sodium Cyanide (NaCN)' originating in or exported from China PR, European Union, Japan and Korea RP.**

**F. No. 6/03/2023-DGTR.**—An application has been filed by Hindusthan Chemical Company and United Phosphorous Limited (hereinafter referred to as the 'applicants'), before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the 'Act') as amended in 1995 and thereafter, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'AD Rules, 1995'), for the initiation of an anti-dumping investigation and the imposition of appropriate anti-dumping duty on imports of "**Sodium Cyanide (NaCN)**" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR, European Union (hereinafter referred to as "EU"), Japan and Korea RP (hereinafter referred to as the 'subject countries')

2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject countries and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration for the present investigation is '**Sodium Cyanide**' which is a moderately strong base. It is a poisonous compound with the formula NaCN. It is white in colour and is a water-soluble solid. Cyanide cation has a high affinity for metals, thus, attributing high toxicity to this base.

4. **Uses:** Sodium Cyanide is used for extraction of gold and silver from their respective ores, in electroplating, heat treatment of metals (case hardening), manufacturing insecticides, dyes, pigments, bulk drugs and in many organic syntheses, agrochemicals, nylon intermediates, gelating compounds, ore flotation and pharmaceutical intermediates.

5. **Tariff classification:** The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 283711 of the Customs Tariff Classification. However, in the past, the PUC has also been imported under other sub-headings as well, such as 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 and 28371910.

6. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of non-confidential version of the anti-dumping application.

**B. LIKE ARTICLE**

7. The applicants have stated that there are no significant differences in the article produced by the applicants and exported from the subject countries. The article produced by the applicants and imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicants has been considered as like article to the product being imported from China PR, EU, Japan and Korea RP.

### C. SUBJECT COUNTRIES

8. The application was originally filed in respect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from China PR, Japan, and Korea RP. Thereafter, during the *prima facie* examination, the investigation team on the basis of the DGCI&S data ascertained that imports from Germany are also above *de minimis* limit and are entering into the domestic market at dumped prices. Hence the subject countries for the purpose of the present investigation are China PR, EU, Japan and Korea RP.

### D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

9. The period of investigation (hereinafter referred to as the POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> October 2021 – 30<sup>th</sup> September 2022 (12 months). Further, the injury investigation period has been proposed as 1<sup>st</sup> April 2019- 31<sup>st</sup> March 2020, 1<sup>st</sup> April 2020- 31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021- 31<sup>st</sup> March 2022 and the POI.

### E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by Hindusthan Chemical Company and United Phosphorous Limited. As per the information provided by the applicants, they are only the producers of the like article in India.

11. The applicants had imported the subject goods in the base year and the year subsequent to it. However, none of the applicants has imported the subject goods in the POI or in the immediately previous year. Further, none of the applicants is related to any of the producer/exporters in the subject countries or any importers of the subject goods in India.

12. Therefore, the applicant domestic producers constitute domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

### F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

#### 13. Normal value

##### I. China PR

- i. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy, and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
- ii. Therefore, the normal value has been constructed based on the estimates of cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

##### II. EU, Japan and Korea RP

- i. The applicants have claimed that the data relating to price in EU, Japan and Korea RP is not available in the public domain. It is also noted that the export price of the subject goods from third countries to other countries is also not available in the public domain.
- ii. Therefore, for purpose of initiation, the normal value has been calculated based on the cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The Authority will further examine the evidence provided by the interested parties and the applicants for the determination of normal value during the investigation.

#### 14. Export Price

- i. The export price for the subject goods has been computed based on the DGCI&S published import data submitted by the applicants with due adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses and bank charges to arrive at the net export price.

#### 15. Dumping Margin

- i. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

### G. INJURY AND CAUSAL LINK

16. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries is significant in



absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject countries as a whole is positive and significant. The production of the domestic industry has declined. The capacity utilisation of the domestic industry has declined. The price suppression and depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns. The market share of the domestic industry is below the demand which it can cater. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. There has also been a significant increase in the inventory levels of the domestic industry. The productivity of applicants has moved in tandem with the changes in the production. The growth of the applicants have been negative in terms of volume as well as price parameters.

17. The import price of the subject imports has not increased in line with the increase in the cost of sales allowing continuous imports from the subject countries despite no demand and supply gap. The continuous low priced imports have not allowed the applicants to utilize its capacity to optimum level. Resultantly, the applicants are operating with idle capacities.

## H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

## I. PROCEDURE

19. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

## J. SUBMISSION OF INFORMATION

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) and [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) with a copy to [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

21. The known producers/exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

22. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

24. Interested parties are further directed to keep regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

## K. TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) and [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) with a copy to [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

29. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the application.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

#### **N. NON-COOPERATION**

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority